THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

NITIN SIR CLASSES

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

मंगलवार, 09 सितम्बर, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 03 Syllabus :GS 2 : Social Justice/ Prelims	केरल का मातृ मृत्यु दर 18 से बढ़कर 30 हो गया
Page 04 Syllabus :GS 2 : International Relations/ Prelims	इजरायल के वित्त मंत्री ने भारत का दौरा किया, द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए
Page 04 Syllabus :GS 2 : International Relations/ Prelims	दुनिया को व्यापार के लिए स्थिर वातावरण की जरूरत है और व्यवहार निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए: जयशंकर
Page 08 Syllabus :GS 2 : Governance & Social Justice / Prelims	नए भारत में 'घरेलू क्षेत्र'
Page 08 Syllabus :GS 2 : Social Justice / Prelims	निजी किंडरगार्टन की लागत अनुपातहीन रूप से अधिक है
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 2 : International Relations	ईरान और भारत, प्राचीन सभ्यताएं और नए क्षितिज

Page 03 : GS 2 :Social Justice / Prelims

केरल को लंबे समय से साक्षरता, स्वास्थ्य परिणामों और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक विकास संकेतकों के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। हालांकि, नवीनतम **नमूना पंजीकरण प्रणाली** (**एसआरएस**) **विशेष बुलेटिन** 2021-23 **से** पता चलता है कि केरल के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में तेज वृद्धि हुई है – प्रति **एक लाख जीवित जन्मों पर** 18 **से** 30 तक। यह विरोधाभास – जहां एक उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य मातृ स्वास्थ्य संकेतकों को खराब करने का रिकॉर्ड करता है – विशेष रूप से **सतत विकास लक्ष्यों** (**एसडीजी** -3: **अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण**) और **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** 2017 के तहत भारत के लक्ष्यों के संदर्भ में गहन जांच की मांग करता है।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **SRS डेटा 2021-23**: केरल का MMR बढ़कर 30 **हो गया**, हालांकि अभी भी सबसे कम (आंध्र प्रदेश के साथ साझा) है।
2. **COVID-19 प्रभाव**: 2021 में, मातृ मृत्यु बढ़कर 220 हो गई (MMR में 51 की वृद्धि)।
3. **गिरती प्रजनन क्षमता और जन्म:** जीवित जन्म सालाना 5-5.5 लाख (एक दशक पहले) से गिरकर 2023 **में** 3.93 **लाख हो गया**, जिसमें और गिरावट का अनुमान है।
4. **डेटा में विसंगति**:
   - **एसआरएस** नमूनाकरण का उपयोग करता है → अक्सर कम/अधिक अनुमान लगाया जाता है।
   - **राज्य स्वास्थ्य विभाग लाइन सूचियाँ** (वास्तविक समय मातृ मृत्यु ऑडिट) प्रति वर्ष ~ 120-140 मातृ मृत्यु लगातार दिखाती हैं।

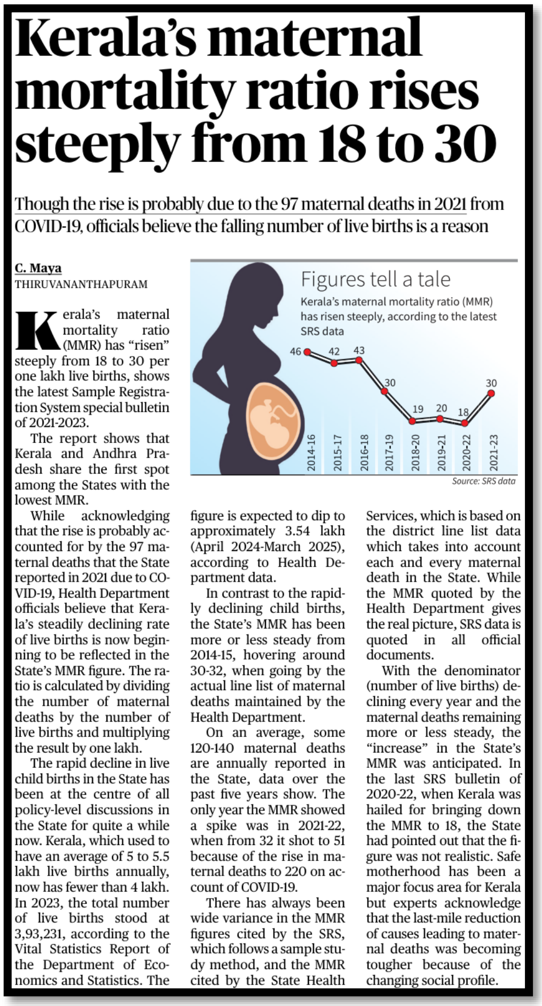

Kerala's maternal mortality ratio rises steeply from 18 to 30

Though the rise is probably due to the 97 maternal deaths in 2021 from COVID-19, officials believe the falling number of live births is a reason

C. Maya
THIRUVANANTHAPURAM

Kerala's maternal mortality ratio (MMR) has "risen" steeply from 18 to 30 per one lakh live births, shows the latest Sample Registration System special bulletin of 2021-2023.

The report shows that Kerala and Andhra Pradesh share the first spot among the States with the lowest MMR.

While acknowledging that the rise is probably accounted for by the 97 maternal deaths that the State reported in 2021 due to COVID-19, Health Department officials believe that Kerala's steadily declining rate of live births is now beginning to be reflected in the State's MMR figure. The ratio is calculated by dividing the number of maternal deaths by the number of live births and multiplying the result by one lakh.

The rapid decline in live child births in the State has been at the centre of all policy-level discussions in the State for quite a while now. Kerala, which used to have an average of 5 to 5.5 lakh live births annually, now has fewer than 4 lakh. In 2023, the total number of live births stood at 3,93,231, according to the Vital Statistics Report of the Department of Economics and Statistics. The figure is expected to dip to approximately 3.54 lakh (April 2024-March 2025), according to Health Department data.

In contrast to the rapidly declining child births, the State's MMR has been more or less steady from 2014-15, hovering around 30-32, when going by the actual line list of maternal deaths maintained by the Health Department.

On an average, some 120-140 maternal deaths are annually reported in the State, data over the past five years show. The only year the MMR showed a spike was in 2021-22, when from 32 it shot to 51 because of the rise in maternal deaths to 220 on account of COVID-19.

There has always been wide variance in the MMR figures cited by the SRS, which follows a sample study method, and the MMR cited by the State Health Services, which is based on the district line list data which takes into account each and every maternal death in the State. While the MMR quoted by the Health Department gives the real picture, SRS data is quoted in all official documents.

With the denominator (number of live births) declining every year and the maternal deaths remaining more or less steady, the "increase" in the State's MMR was anticipated. In the last SRS bulletin of 2020-22, when Kerala was hailed for bringing down the MMR to 18, the State had pointed out that the figure was not realistic. Safe motherhood has been a major focus area for Kerala but experts acknowledge that the last-mile reduction of causes leading to maternal deaths was becoming tougher because of the changing social profile.

Figures tell a tale
Kerala's maternal mortality ratio (MMR) has risen steeply, according to the latest SRS data

2014-16	2015-17	2016-18	2017-19	2018-20	2019-21	2020-22	2021-23
46	42	43	30	19	20	18	30

Source: SRS data

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर):** प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु।
- **भारत की प्रगति**:
  - 2014-16 → एमएमआर: 130
  - 2019-21 → एमएमआर: 97
  - लक्ष्य: <70 (2030 तक एसडीजी)।
- **मातृ स्वास्थ्य के लिए योजनाएं**:
  - **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** – संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन।
  - **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** - मुफ्त परिवहन और देखभाल।
  - **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** - निश्चित दिनों में गुणवत्ता एएनसी।
  - **लक्ष्य कार्यक्रम** - लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी केयर में सुधार।
- **मातृ मृत्यु दर के निर्धारक:**

- चिकित्सा: रक्तस्राव, सेप्सिस, एक्लम्पसिया, बाधित प्रसव।
- सामाजिक: कम उम्र में शादी, खराब पोषण, कम एएनसी कवरेज।
- जनसांख्यिकीय: प्रजनन क्षमता में गिरावट, बढ़ती माताएं, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **प्रजनन क्षमता में गिरावट का संख्यात्मक प्रभाव**:
   - स्थिर मातृ मृत्यु (~ 120-140 सालाना) **और घटते जन्म** के साथ, **हर प्रभाव** कृत्रिम रूप से एमएमआर को ऊपर की ओर धकेलता है।
   - इसलिए, यह वृद्धि जरूरी नहीं कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट हो, बल्कि एक सांख्यिकीय परिणाम हो।
2. **गर्भधारण की बदलती सामाजिक रूपरेखा**:
   - केरल में अब **अधिक उम्र में कम गर्भधारण होता है**, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा जैसी सह-रुग्णता का प्रसार अधिक होता है।
   - ये जोखिम कारक मातृ मृत्यु को और कम करना कठिन बनाते हैं ("अंतिम-मील चुनौती")।
3. **COVID-19 शॉक**:
   - कोविड के कारण 2021 में 97 मातृ मृत्यु ने सीधे तौर पर एमएमआर को बढ़ा दिया।
   - स्वास्थ्य प्रणाली के झटकों के लिए मातृ स्वास्थ्य की भेद्यता को दर्शाता है।
4. **नीति विरोधाभास**:
   - जबकि केरल अभी भी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, सापेक्ष **वृद्धि चिंता** पैदा करती है।
   - केवल अनुपात ही नहीं, बल्कि **पूर्ण मातृ मृत्यु में कमी** के महत्व पर प्रकाश डालता है।
5. **डेटा विश्वसनीयता मुद्दा**:
   - **एसआरएस बनाम राज्य डेटा** → सवाल उठाता है कि किस डेटासेट को नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए।
   - यूपीएससी के लिए, **भारत में** सांख्यिकीय शासन के मुद्दे को दर्शाता है।

निष्कर्ष

केरल का बढ़ता एमएमआर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विफलता कम है और **जनसांख्यिकीय संक्रमण**, **घटते जन्म के विभाजक प्रभाव और महामारी से संबंधित झटकों का प्रतिबिंब अधिक है**। राज्य मातृ स्वास्थ्य में अग्रणी बना हुआ है, लेकिन एक छोटी, उच्च जोखिम वाली मातृ आबादी के बीच मौतों को और कम करने की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत के लिए, सबक दो गुना है:

- मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अब **उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ाना।
- एसआरएस और राज्य-स्तरीय मृत्यु ऑडिट दोनों को एकीकृत करने वाली मजबूत डेटा प्रणाली साक्ष्य-आधारित नीति के लिए महत्वपूर्ण है।

केरल का मामला इस बात को रेखांकित करता है कि 2030 **तक एमएमआर** <70 **के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए** चिकित्सा जोखिम कारकों और जनसांख्यिकीय बदलाव दोनों **को संबोधित करने की आवश्यकता होगी**, जिससे मातृ स्वास्थ्य न केवल एक स्वास्थ्य मुद्दा बन जाएगा, बल्कि एक **सामाजिक-जनसांख्यिकीय नीति चुनौती बन जाएगी**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से भारत में मातृ और नवजात स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से है?

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

2. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

3. लक्ष्य कार्यक्रम

4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 1 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (क)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: केरल के मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में राज्य के मजबूत स्वास्थ्य संकेतकों के बावजूद 18 से 30 तक की वृद्धि देखी गई है। जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें और 2030 तक एमएमआर को 70 से कम करने के भारत के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय सुझाएं। **(250 शब्द)**

यूपीएससी निबंध अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: घटती प्रजनन क्षमता, जनसांख्यिकीय बदलाव और स्वास्थ्य समानता - भारत की मातृ और शिशु स्वास्थ्य नीति के लिए चुनौतियां। **(1200 शब्द)**

Page 04 :GS 2 : International Relations/ Prelims

भारत और इज़राइल ने तीन दशकों से अधिक समय तक (1992 से) पूर्ण राजनयिक संबंधों को चिह्नित करते हुए अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को काफी गहरा किया है। हाल ही **में नई दिल्ली में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजरायली समकक्ष बेजलेल स्मोट्रिच के बीच** द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर जब यह **पहला बीआईटी है जिसे भारत ने अपने नए मॉडल निवेश संधि ढांचे के तहत ओईसीडी सदस्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं**।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

Israeli Finance Minister visits India, signs bilateral investment treaty

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Days after Israel intensified its ongoing military operation in Gaza Strip, India hosted Israeli Minister of Finance Bezalel Smotrich, who held talks with his Indian counterpart, Nirmala Sitharaman, and signed a Bilateral Investment Agreement here on Monday. Mr. Smotrich is leading a delegation of Israeli officials that includes the Chief Economist of the Israeli Ministry of Finance, Shmuel Abramzon.

"The agreement we signed expresses our shared vision for innovative and secure economic development. This is a strategic step that will open new doors for both Israeli and Indian investors, strengthen Israeli exports, and provide businesses on both sides with certainty and tools to develop in the world's fastest-growing markets. India is a growing economic powerhouse, and cooperation with it is a tremendous opportunity for the State of Israel," said Mr. Smotrich after signing the agreement with Ms. Sitharaman.

Trade boost: Bezalel Smotrich and Nirmala Sitharaman during the signing ceremony in New Delhi on Monday. PIB/PTI

Mr. Smotrich's arrival in India coincided with the launch of a new phase of Israeli military campaign in the Gaza Strip as the Israeli Defence Forces (IDF) are trying to evacuate the Gaza City in order to create a sanitised zone, which has million-plus civilians facing serious issues like bombing raids and starvation.

Significant outreach

Mr. Smotrich's visit to India is a sign of significant outreach by Israel as he was banned by the United Kingdom, Australia, New Zealand, Norway and Canada in June this year.

The Ministry of External Affairs is yet to respond to a query from *The Hindu* about the visit but highly placed Israeli sources said that Israel is in the process of throwing open new sectors of its economy, especially the construction sector, which will generate investment and employment opportunities for Indians. Israel, which started the current military campaign after the October 7, 2023 attack by Hamas, has hired a large number of Indian blue collar workers in the last two years.

Mr. Smotrich also met Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, who in a message said, "Our discussions focused on further strengthening trade and investment ties between our nations."

New model

"A new Bilateral Investment Agreement signed by Israel's Minister of Finance Bezalel Smotrich and India's Finance Minister will facilitate reciprocal investments between investors from both countries. Israel is the first OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] member state with which India has signed this strategic agreement, in accordance with India's new model for investment treaties," said the Israeli Ministry of Finance. Mr. Smotrich announced that the Israeli Ministry of Finance is examining the possibility of opening a representation office in India.

The Israeli Ministry further said that the new agreement will replace the previous agreement that was signed in 1996.

1. **बीआईटी (2025) पर हस्ताक्षर**: पारस्परिक निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है, इजरायली निर्यात को मजबूत करता है, और भारतीय व्यवसायों को उच्च तकनीक वाले इजरायली क्षेत्रों तक अधिक पहुंच प्रदान करता है।
2. **भू-राजनीतिक संवेदनशीलता**: यह यात्रा गाजा में इजरायल के चल रहे सैन्य अभियानों के बीच हो रही है, जिसमें भारत द्वारा मानवीय चिंताओं के साथ आर्थिक जुड़ाव को संतुलित करने के बारे में राजनयिक सवाल उठाए गए हैं।
3. **इज़राइली आउटरीच**: इज़राइल भारतीय निवेश और रोजगार के लिए नए क्षेत्रों (जैसे, निर्माण) खोल रहा है; भारतीय ब्लू-कॉलर श्रमिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती पहले से ही चल रही है।
4. **उच्च स्तरीय व्यस्तताएं**: इजरायल के वित्त मंत्री ने न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की, आर्थिक फोकस को रेखांकित किया।
5. **संस्थागत परिवर्तन**: नया समझौता **1996 के भारत-इज़राइल बीआईटी** की जगह लेता है, जो भारत की **2016 के बाद की बीआईटी नीति बदलाव** (पुरानी संधियों के तहत कई निवेशक-राज्य विवादों के बाद) के साथ संरेखित है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी):** निजी निवेशकों द्वारा सीमा पार निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले दो देशों के बीच कानूनी समझौता।
- **भारत का नया मॉडल बिट (2016):**
  - निवेश की संकीर्ण परिभाषा (उद्यम-आधारित)।
  - अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले स्थानीय उपचार की अनिवार्य थकावट।
  - "सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र" खंड (MFN) को बाहर करता है।
  - पहले के बीआईटी के तहत **व्हाइट इंडस्ट्रीज बनाम भारत** जैसे विवादों के बाद **संप्रभु नीति स्थान की** रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **भारत-इज़राइल संबंध:**
  - व्यापार: ~$10.7 बिलियन (2023-24, भारत के साथ व्यापार अधिशेष का आनंद ले रहा है)।
  - रक्षा: इज़राइल भारत को शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता (ड्रोन, मिसाइल, रडार) में से एक है।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी: इंडो-इज़राइल इंडस्ट्रियल आर एंड डी फाउंडेशन (i4RD)।
  - प्रवासी: इज़राइल में भारतीय मूल के ~85,000 यहूदी, और निर्माण/कृषि में भारतीय कार्यबल बढ़ रहा है।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **आर्थिक महत्व**:
   - भारत को इजरायल के हाई-टेक इकोसिस्टम **(साइबर सुरक्षा, एआई, जल प्रौद्योगिकी, कृषि-तकनीक**) तक पहुंच प्राप्त है।
   - इजरायल के निवेशकों को भारत के **बड़े बाजार, विनिर्माण आधार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से लाभ होता है**।
2. **भू-राजनीतिक कोण**:
   - स्मोट्रिच की यात्रा विवादास्पद है - चरमपंथी टिप्पणियों के कारण कई पश्चिमी देशों द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत की भागीदारी **विदेश नीति में व्यावहारिकता और स्वायत्तता का संकेत देती है**, जो रूस-यूक्रेन युद्ध पर उसके रुख के समान है।
   - संतुलन अधिनियम: गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता का समर्थन करते हुए इजरायल के साथ संबंधों को गहरा करना।
3. **श्रम गतिशीलता**:
   - इजराइल का कंस्ट्रक्शन बूम + वर्कर्स की कमी → भारतीय लेबर की मांग।
   - अवसर बढ़ाता है लेकिन संघर्ष क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ाता है।
4. **नीति आयाम:**
   - पहला ओईसीडी बीआईटी भारत के नए बीआईटी मॉडल के बारे में झिझक रहे अन्य विकसित देशों के लिए विश्वास निर्माण →।
   - भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) **पर रुकी हुई वार्ता को उत्प्रेरित कर सकता** है।

निष्कर्ष

भारत-इजरायल बीआईटी भारत की आर्थिक साझेदारी में विविधता लाने की दिशा में एक **प्रतीकात्मक और ठोस कदम** है । जहां यह निवेश प्रवाह और तकनीकी सहयोग को मजबूत करता है, वहीं यह वैश्विक विवादों के बावजूद इजरायल के साथ जुड़ने के भारत की **स्वतंत्र विदेश नीति के रुख** को भी उजागर करता है। आगे बढ़ते हुए, चुनौती आपसी आर्थिक लाभ के लिए इस संधि का लाभ उठाने की होगी, जबकि यह सुनिश्चित करना होगा कि गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की वैश्विक छवि संतुलित रहे।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत-इजरायल संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं?

1. कृषि और जल प्रौद्योगिकी

2. साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

3. रक्षा प्रौद्योगिकी और हथियारों की आपूर्ति

4. अंतरिक्ष सहयोग

सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : घ)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: भारत ने हाल ही में इजरायल के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, जो नए मॉडल बीआईटी ढांचे के तहत ओईसीडी सदस्य के साथ इस तरह का पहला समझौता है। भारत की निवेश नीति और विदेशी संबंधों के संदर्भ में इस समझौते के महत्व पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page : 04: GS 2 : International Relations/ Prelims

अमेरिका के नेतृत्व में बढ़ते टैरिफ युद्धों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ते व्यवधानों की पृष्ठभूमि में, विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने ब्राज़ील द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्थिर, पूर्वानुमानित और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के महत्व पर ज़ोर दिया। उनकी टिप्पणियाँ एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत के रुख को दर्शाती हैं, जिसमें व्यापार व्यवधानों, संघर्ष-जनित असुरक्षाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलताओं की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

World needs stable environment for trade and practices must be fair, transparent: Jaishankar

Press Trust of India
NEW DELHI

The world is seeking a stable and predictable environment for trade, and economic practices should be fair, transparent and to everyone's benefit, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Monday, against the backdrop of increasing global concerns over Washington's tariff tussle.

In an address at a virtual BRICS summit, the Minister said India strongly believes that the international trading system's foundational principles of non-discriminatory and rules-based norms must be protected and that there is a need to create more resilient and reliable supply chains.

Mr. Jaishankar represented Prime Minister Narendra Modi at the summit that saw participation of Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and several other leaders of the grouping.

It was convened by Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva to discuss trade disruptions triggered by U.S.' policies on trade and tariff. The U.S. slapped 50% tariffs on Brazilian exports like in the case of India.

Virtual meeting: S. Jaishankar addresses the BRICS Summit in New Delhi on Monday. ANI

'Balancing act'

Mr. Jaishankar's participation at the summit in place of Mr. Modi is seen as part of New Delhi's "balancing act" with the Trump administration increasingly getting suspicious about the BRICS.

In his remarks, Mr. Jaishankar called for urgent resolution to ongoing conflicts, adding the Global South has experienced a deterioration in its food, energy and fertilizer security. However, the major focus of his speech was on trade.

"The international trading system is based on the foundational principles of open, fair, transparent, non-discriminatory, inclusive, equitable and a rules-based approach with special and differential treatment for developing countries," Mr. Jaishankar said.

The Minister also said that the "state of the world today is a cause for genuine concern".

He listed devastating impact of the Covid pandemic, major conflicts in Ukraine and the Middle East and volatility in trade and investment flows as well as extreme climate events as some of the major challenges facing the globe in the last few years.

"In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself," he said.

"It is this cumulative concern that BRICS is now discussing," he added.

The Minister argued that the working of international organisations in the last few years has witnessed "major shortfalls" in many areas.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **शिखर सम्मेलन फोकस**: अमेरिकी टैरिफ नीतियों **के कारण व्यापार व्यवधान** (ब्राजील के निर्यात पर 50% टैरिफ; भारत के लिए समान चिंताएं)।
2. **जयशंकर की टिप्पणी**:
    - निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं **का आह्वान किया**।
    - विकासशील देशों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन** और विशेष उपचार पर **प्रकाश डाला**।
    - व्यापक संकटों के साथ व्यापार अस्थिरता: COVID-19, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष, जलवायु झटके।
3. **बैलेंसिंग एक्ट**: भारत के पीएम ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया; जयशंकर की भागीदारी भारत की सावधानीपूर्वक कूटनीति को दर्शाती है, जो ब्रिक्स के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करती है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **ब्रिक्स**: 2009 में स्थापित (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका; मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए 2024 में विस्तार किया गया)।

- **विस्तार के लिए स्मरणीय (2024):** *"SEEISU"* = **सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, SU** = यूएई
- **उद्देश्य:** वैश्विक शासन में सुधार, बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, अंतर-ब्रिक्स व्यापार को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक व्यापार सिद्धांत:**
  - **डब्ल्यूटीओ का ढांचा** नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, एमएफएन सिद्धांत, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार → है।
  - टैरिफ युद्ध बहुपक्षवाद को कमजोर करते हैं।
- **ब्रिक्स में भारत के हित:**
  - ग्लोबल साउथ की आवाज।
  - पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों (आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ) के लिए प्रतिसंतुलन।
  - ऊर्जा, भोजन, उर्वरक सुरक्षा।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **वैश्विक व्यापार अनिश्चितता**:
   - अमेरिकी टैरिफ ब्राजील, भारत और अन्य से निर्यात को बाधित करते हैं → डब्ल्यूटीओ को कमजोर करते हैं।
   - विकासशील देशों पर ब्रिक्स जैसे सामूहिक मंच तलाशने के लिए प्रेरित किया।
2. **भारत की राजनयिक स्थिति**:
   - भारत वैश्विक व् यापार में **निष्पक्षता और पारदर्शिता** पर जोर देता है।
   - अमेरिका के साथ सीधे टकराव से बचता है लेकिन ब्रिक्स की आलोचना के साथ संरेखित करता है।
   - भारत की रणनीतिक स्वायत्तता **को दर्शाता है**: प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंधों के साथ ग्लोबल साउथ एकजुटता को संतुलित करना।
3. **बहुपक्षवाद में चुनौतियाँ**:
   - विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र पंगु हो गया है।
   - महामारी + युद्धों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को उजागर किया।
   - जलवायु के झटके विकासशील देशों के लिए खाद्य और उर्वरक सुरक्षा को खराब करते हैं।
4. **भारत के लिए निहितार्थ:**
   - भारत व्यापार भागीदारों में विविधता लाना और लचीलेपन को मजबूत करना चाहता है।
   - वैश्विक शासन में सुधार के लिए ब्रिक्स का उपयोग करने का अवसर, लेकिन आंतरिक मतभेद (चीन-रूस बनाम भारत-पश्चिम झुकाव) प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

निष्कर्ष

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जयशंकर की टिप्पणी एक **निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली** के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। जबकि टैरिफ युद्ध और वैश्विक संघर्ष बहुपक्षीय संस्थानों में विश्वास को खत्म कर रहे हैं, भारत खुद को **विकसित और विकासशील दुनिया के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : ब्रिक्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्रिक्स की स्थापना 2009 में एक औपचारिक समूह के रूप में की गई थी।

2. इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

3. ब्रिक्स समूह ने हाल ही में मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : b)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: वैश्विक व्यापार व्यवधानों और बहुपक्षवाद विफलताओं की चुनौतियों का समाधान करने में ब्रिक्स की भूमिका का मूल्यांकन करें। ब्रिक्स के भीतर भारत के लिए अवसर और सीमाएँ क्या हैं? **(150 शब्द)**

Page 08 :GS 1 : Social Issues / Prelims

जबकि भारत का सार्वजनिक विमर्श अक्सर **"नारी शक्ति"** और "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" पर प्रकाश डालता है, घरेलू क्षेत्र के भीतर संरचनात्मक असमानताओं **पर** ध्यान नहीं दिया जाता है। हाल के बयान (उदाहरण के लिए, बड़े परिवारों के लिए कॉल) और सर्वेक्षण (उदाहरण के लिए, **टाइम यूज सर्वे 2024**, एनएफएचएस-5) बयानबाजी और वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट अंतर को प्रकट करते हैं। यह मुद्दा घरेलू जिम्मेदारियों से परे है - यह श्रम अधिकारों, आर्थिक उत्पादकता, लैंगिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करता है।

The 'domestic sphere' in a new India

Under the present regime, when a myriad socio-economic and political challenges confront the people of India, developments in the "domestic sphere" are often put on the back burner in agendas of resistance. This allows those who are in power to hijack the concept of "nari shakti" and make claims of "women-led development" even as they keep intact an entirely regressive approach to women in the "domestic sphere". The latest example of this is a statement by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief, in August 2025, where he said that in order to ensure the "survival of the civilization", families need to have at least three children – as though women are reproduction machines with little or no choice. It would have been more appropriate for Mohan Bhagwat to have spoken about the survival of families and, specifically, of women within the home.

An inexplicable silence

An average of 7,000 women have died every year, from 2017 to 2022, in horrendous cases where they are burnt – legally known as dowry deaths. So, 35,000 women are dead – it is not only their *sindoor* that has been wiped out; a woman's life has been terminated. The National Family Health Survey-5 noted that 30% of the women surveyed reported violence by an intimate partner but only 14% made a police complaint. A third of the over 4.45 lakh cases of registered crimes against women are of domestic violence. But have you heard even one word being spoken by even a single RSS or Bharatiya Janata Party (BJP) leader, man or woman, against violence within the home? These are the people who are loud and clear in speaking against consensual inter-community relationships – which they term as love jihad – but never say a word about any instance of violence within the home or within the community as this would not fit in with the majoritarian ideology based on the Manu Smriti which they expound.

There has been little change since the days when the *manuvadi* forefathers of those now in power railed against B.R. Ambedkar for the "demolition of Hindu ideology", for his proposals in the Hindu Reform Bills granting women the right to divorce and abolishing caste as a requirement for a valid marriage. Cultures that pressurise women to stay in violent marriages, to "adjust" because of the sacramental nature of marriage", that condone, through their silence, so-called honour crimes in self-choice inter-caste marriages are intrinsic to the ideological platform of the Hindutva eco-system today. We can see this in efforts to dilute laws against domestic violence in the name of "misuse" and also the official argument in the Supreme Court case opposing the demand to criminalise marital rape as being "against the institution of marriage" and "Indian culture".

Brinda Karat

is a senior leader of the CPI(M)

The policies of the government have an impact on the 'domestic sphere' and need to be called out as women in India face gross discrimination

Another aspect of the "domestic sphere" – the work women do within and outside the home – has been highlighted by the recent Time Use survey (TUS) 2024. The percentage of men and women in different activities has been calculated using the average age of all those surveyed. Taking the age group (15-59 years) of all the women surveyed, 25% were in "employment and related activities" working an average of five hours. The percentage of women working in family enterprises was 23%; women in this category put in a little less than two hours of work. The work done in these two categories is recognised to be economically productive and is included in the System of National Accounts (SNA). The corresponding data for men are an average of 75% men in the first category, working on an average of eight hours a day. In family enterprises, 14% of men work for an average of two hours a day. That is the end of the work day for the majority of men.

Women and the burden of work

The TUS lists two other work-related categories – unpaid domestic services (cooking, cleaning, washing) and unpaid caregiving services. Here, 93% of all women put in an average of seven hours a day in the first category and 41% of women put in two and a half hours in unpaid domestic care. The corresponding figure for men is that 70% of men do not do any domestic work. The 30% who do domestic work, put in less than one and a half hours a day. In the unpaid caregiving category, 79% of men do no "unpaid caregiving" while the 21% who do, put in an average of an hour and 14 minutes a day. If one takes the average for all men, one has this data: in the "domestic sphere" men do 26 minutes of domestic work in a day and less than 16 minutes of unpaid care giving.

The TUS has other categories but taking them all together, the conclusion is that the total working hours put in by women are more than men, and that women spend less time in eating, sleeping, and leisure than men. These are the basics. Further analysis will show the division of work in different income groups, especially for Scheduled Tribes and Scheduled Caste men and women. Such a study would reveal the class and caste differences in the use of time, with women of the labouring classes shouldering a disproportionately higher share of work than men.

One has to look at the utter hypocrisy of the Narendra Modi government in its presentation of the survey findings. Months before the full report was published, the official government agency, the Press Information Bureau, in its press release dated February 25, 2025 (with a summary of the survey) headlined it as: "More acknowledgement of care-giving activities regardless of gender in Indian families". Further, the inequalities in time use were sought to be glorified with the line, "...This corroborates the Indian social fabric wherein most of the care-giving responsibilities for household members are borne by the females of the household." As far as the official viewpoint of the BJP government is concerned, that men give any time at all for care-giving, even if it is for an average of just 15 minutes, shows the greatness of the "Indian family", and that women do three times the work in domestic and care-giving as men is something to be proud of – i.e., the Indian social fabric.

In an extension of this approach to public policy, the millions of women who take on the responsibility of child-care services in anganwadi, mid-day meal services and as Accredited Social Health Activists (ASHA), are considered to be "social volunteers" and not workers. They are given a measly amount as an honorarium and not as a minimum wage. Finally, they are not recognised as government employees. Thus, what is considered to be a "natural" task for women in the domestic sphere gets translated into low-wage work in care services in the public sphere.

A gross undervaluation

Such an approach suits the capitalist too. The State Bank of India, in a survey in 2023, showed that if unpaid work done by women was monetised it would amount to over 7% of the country's GDP or ₹22.5 lakh crore a year. It also points to the undervaluation of the essential role played by a woman's unpaid domestic work in the social reproduction of labour. Her work is not considered when a minimum wage is fixed. Typically, such a wage covers the bare subsistence needs of a worker and family, to keep him healthy enough to work the next day too. This "subsistence " level is actually subsidised by the woman's unaccounted for and invisibilised domestic and care-giving work. The invisible component of a woman's domestic work is what keeps the cost of subsistence and wages low. Thus, the struggle for a fair minimum wage has a direct relation to recognition of the invisible work that women do.

The policies of the government have a direct impact on the "domestic sphere" and need to be called out. The alternative lies in: first, cultural, social and policy interventions to prevent and eliminate violence against women within families; second, the equal right to work of men and women as primary workers with equal wages; third, the provision of easily accessible universal facilities for the care of children and the aged provided by the state; fourth, the provision of quality health care and education facilities; fifth, the promotion of cultures which encourage the sharing of domestic responsibility between men and women as opposed to the "social fabric" argument of the right-wing forces, and finally, justice to all scheme workers in child care and health services for minimum wages and benefits as government employees.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **NFHS-5 (2019-21):** 30% महिलाएं अंतरंग साथी हिंसा की रिपोर्ट करती हैं; केवल 14% शिकायत दर्ज करती हैं।
2. **दहेज से होने वाली मौत:** ~ 7,000 महिलाएं सालाना (2017-22)।
3. **समय उपयोग सर्वेक्षण (2024):**
    - 93% महिलाएं **अवैतनिक घरेलू सेवाएं** (औसत 7 घंटे/दिन) करती हैं।
    - 41% अवैतनिक देखभाल करते हैं (औसत 2.5 घंटे/दिन)।
    - पुरुष: केवल 30% घरेलू काम करते हैं (औसत <1.5 घंटे / दिन)।
    - पुरुषों > महिलाओं के **कुल काम के घंटे**, फिर भी कम आंका गया।
4. **सरकारी कथा:** पीआईबी रिलीज (फरवरी 2025) ने असमानता को नजरअंदाज करते हुए महिलाओं के घरेलू काम को "भारतीय सामाजिक ताने-बाने की ताकत" के रूप में तैयार किया।
5. **नीति प्रतिबिंब:** आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील वर्कर्स को "स्वयंसेवक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि सरकारी कर्मचारियों के रूप में।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (कोई भेदभाव नहीं), 39 (डी) (समान काम के लिए समान वेतन), 42 (मातृत्व राहत)।
- **कानूनी ढांचा:**
    - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
    - दहेज निषेध अधिनियम, 1961
    - वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर बहस।
- **आर्थिक कोण:**
    - SBI 2023 रिपोर्ट: अवैतनिक काम का मुद्रीकरण = GDP **का 7% (₹22.5 लाख करोड़)।**
    - अदृश्य काम निर्वाह **मजदूरी को कम रखता है**, पूंजीवाद को सब्सिडी देता है।
- **वैश्विक संदर्भ:**
    - संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 5 (लैंगिक समानता)।
    - आईएलओ अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम को मान्यता देने का आह्वान करता है।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **अदृश्य बोझ:** अवैतनिक घरेलू/देखभाल कार्य में महिलाओं की अनुपातहीन हिस्सेदारी औपचारिक श्रम बाजार में भागीदारी को कम → है।
2. **हिंसा और चुप्पी:** घरेलू हिंसा बनी हुई है, फिर भी "लव जिहाद" या अंतर-जातीय विवाह की तुलना में बहुत कम राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त होती है।
3. **वैचारिक आयाम**: विवाह में "समायोजित" करने के लिए सांस्कृतिक दबाव, तलाक के अधिकारों का प्रतिरोध, और वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की अनिच्छा प्रतिगामी मानदंडों को दर्शाती है।
4. **नीति विरोधाभास**:
    - असमान श्रम वितरण का आधिकारिक महिमामंडन।
    - आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक सार्वजनिक भूमिका के बावजूद कम वेतन मिलता है।
5. **आर्थिक अवमूल्यन:** महिलाओं का अवैतनिक काम घरेलू और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देता है, फिर भी **सकल घरेलू उत्पाद की गणना** और **न्यूनतम मजदूरी नीति में अदृश्य रहता है**।

आगे की राह / निष्कर्ष

घरेलू क्षेत्र राजनीतिक है - यह अर्थव्यवस्था और समाज में महिलाओं की भागीदारी को आकार देता है। इस अंतर को पाटने के लिए आवश्यक है:

- घरेलू हिंसा के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन।
- नीति और मजदूरी में महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता देना।
- सार्वभौमिक चाइल्डकैअर, बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं।
- समान मजदूरी, औपचारिक काम में महिलाओं के लिए समान अवसर।
- पुरुषों को घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक अभियान।
- योजना कार्यकर्ताओं (आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी) के लिए औपचारिक श्रमिक का दर्जा और उचित मजदूरी।

भारत को वास्तव में "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" **को प्राप्त करने के लिए**, बयानबाजी को उन नीतियों में तब्दील करना चाहिए जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह महिलाओं के योगदान को महत्व देती **हैं**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में महिलाओं के अवैतनिक कार्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एसबीआई (2023) ने अनुमान लगाया कि महिलाओं द्वारा अवैतनिक काम का मुद्रीकरण भारत के सकल घरेलू उत्पाद का ~7% होगा।

2. NFHS-5 के अनुसार, 30% से अधिक महिलाओं ने घरेलू हिंसा की सूचना दी।

3. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रम कानूनों के तहत सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : क)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं का गंभीर विश्लेषण करें जो घरेलू हिंसा को बनाए रखते हैं और भारत में महिलाओं के काम को कम करते हैं। सुधारों का सुझाव दें। **(150 शब्द)**

Page 09 : GS 2 : Social Justice/ Prelims

शिक्षा एक **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)** और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण चालक दोनों है। हालाँकि, **व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025 के हालिया निष्कर्ष स्कूली** शिक्षा व्यय में एक स्पष्ट असंतुलन को उजागर करते हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि **निजी किंडरगार्टन की लागत अनुपातहीन रूप से अधिक है**, निजी और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर पूर्व-प्राथमिक स्तर पर व्यापक है और उच्च स्तर पर कम हो रहा है। यह **भारत के निजी शिक्षा क्षेत्र में** सामर्थ्य, इक्विटी और संभावित मुनाफाखोरी के बारे में चिंता पैदा करता है।

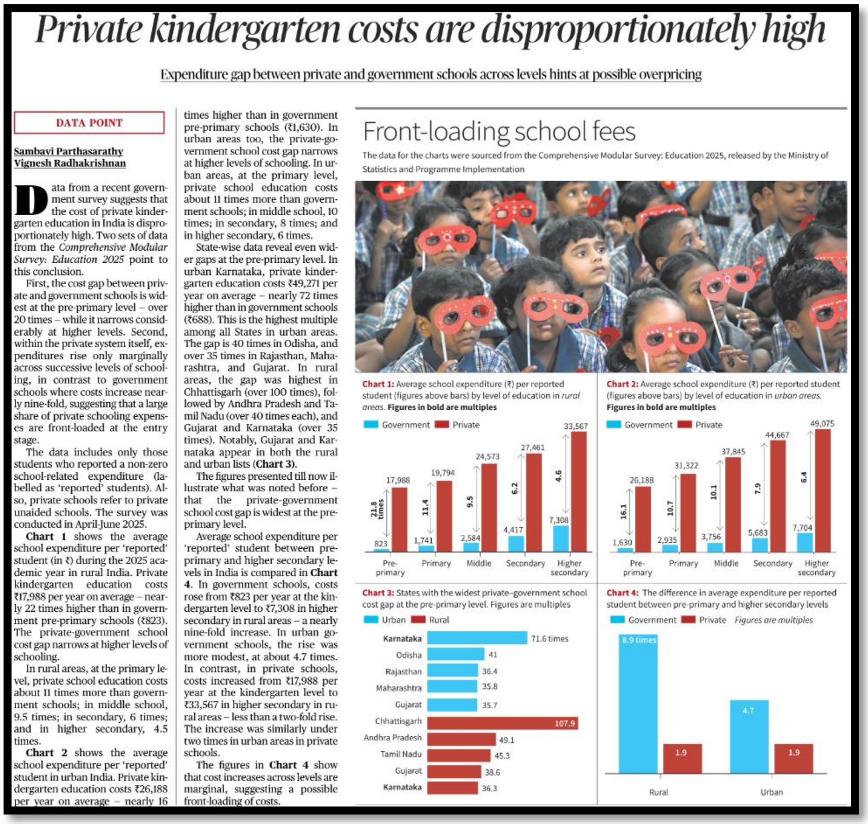

Private kindergarten costs are disproportionately high

Expenditure gap between private and government schools across levels hints at possible overpricing

DATA POINT

Sambavi Parthasarathy
Vignesh Radhakrishnan

Data from a recent government survey suggests that the cost of private kindergarten education in India is disproportionately high. Two sets of data from the *Comprehensive Modular Survey: Education 2025* point to this conclusion.

First, the cost gap between private and government schools is widest at the pre-primary level – over 20 times – while it narrows considerably at higher levels. Second, within the private system itself, expenditures rise only marginally across successive levels of schooling, in contrast to government schools where costs increase nearly nine-fold, suggesting that a large share of private schooling expenses are front-loaded at the entry stage.

The data includes only those students who reported a non-zero school-related expenditure (labelled as 'reported' students). Also, private schools refer to private unaided schools. The survey was conducted in April-June 2025.

Chart 1 shows the average school expenditure per 'reported' student (in ₹) during the 2025 academic year in rural India. Private kindergarten education costs ₹17,988 per year on average – nearly 22 times higher than in government pre-primary schools (₹823). The private-government school cost gap narrows at higher levels of schooling.

In rural areas, at the primary level, private school education costs about 11 times more than government schools; in middle school, 9.5 times; in secondary, 6 times; and in higher secondary, 4.5 times.

Chart 2 shows the average school expenditure per 'reported' student in urban India. Private kindergarten education costs ₹26,188 per year on average – nearly 16 times higher than in government pre-primary schools (₹1,630). In urban areas too, the private-government school cost gap narrows at higher levels of schooling. In urban areas, at the primary level, private school education costs about 11 times more than government schools; in middle school, 10 times; in secondary, 8 times; and in higher secondary, 6 times.

State-wise data reveal even wider gaps at the pre-primary level. In urban Karnataka, private kindergarten education costs ₹49,271 per year on average – nearly 72 times higher than in government schools (₹688). This is the highest multiple among all States in urban areas. The gap is 40 times in Odisha, and over 35 times in Rajasthan, Maharashtra, and Gujarat. In rural areas, the gap was highest in Chhattisgarh (over 100 times), followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu (over 40 times each), and Gujarat and Karnataka (over 35 times). Notably, Gujarat and Karnataka appear in both the rural and urban lists (**Chart 3**).

The figures presented till now illustrate what was noted before – that the private-government school cost gap is widest at the pre-primary level.

Average school expenditure per 'reported' student between pre-primary and higher secondary levels in India is compared in **Chart 4**. In government schools, costs rose from ₹823 per year at the kindergarten level to ₹7,308 in higher secondary in rural areas – a nearly nine-fold increase. In urban government schools, the rise was more modest, at about 4.7 times. In contrast, in private schools, costs increased from ₹17,988 per year at the kindergarten level to ₹33,567 in higher secondary in rural areas – less than a two-fold rise. The increase was similarly under two times in urban areas in private schools.

The figures in **Chart 4** show that cost increases across levels are marginal, suggesting a possible front-loading of costs.

Front-loading school fees

The data for the charts were sourced from the Comprehensive Modular Survey: Education 2025, released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation

Chart 1: Average school expenditure (₹) per reported student (figures above bars) by level of education in *rural areas*. **Figures in bold are multiples**

Level	Government	Private	Multiple
Pre-primary	823	17,988	21.8 times
Primary	1,741	19,794	11.4
Middle	2,584	24,573	9.5
Secondary	4,417	27,461	6.2
Higher secondary	7,308	33,567	4.6

Chart 2: Average school expenditure (₹) per reported student (figures above bars) by level of education in *urban areas*. **Figures in bold are multiples**

Level	Government	Private	Multiple
Pre-primary	1,630	26,188	16.1
Primary	2,935	31,322	10.7
Middle	3,756	37,845	10.1
Secondary	5,683	44,667	7.9
Higher secondary	7,704	49,075	6.4

Chart 3: States with the widest private-government school cost gap at the pre-primary level. Figures are multiples

State	Urban	Rural
Karnataka	71.6 times	
Odisha	41	
Rajasthan	36.4	
Maharashtra	35.8	
Gujarat	35.7	
Chhattisgarh		107.9
Andhra Pradesh		49.1
Tamil Nadu		45.3
Gujarat		38.6
Karnataka		36.3

Chart 4: The difference in average expenditure per reported student between pre-primary and higher secondary levels

Government, Private. *Figures are multiples*

	Government	Private
Rural	8.9 times	1.9
Urban	4.7	1.9

करेंट अफेयर्स इनसाइट्स

1. **निजी बनाम सरकारी लागत अंतर (पूर्व-प्राथमिक):**
   - ग्रामीण: निजी किंडरगार्टन की लागत ₹17,988/वर्ष बनाम सरकारी स्कूलों में ₹823 (22x अंतर) है।
   - शहरी: ₹26,188 बनाम ₹1,630 (16x अंतर)।
   - चरम मामले: ग्रामीण छत्तीसगढ़ (>100x गैप), शहरी कर्नाटक (72x)।
2. **स्तरों पर रुझान:**

- सरकारी स्कूल: लागत लगातार बढ़ रही है (ग्रामीण में 9 गुना, शहरी में पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक 4.7 गुना)।
- निजी स्कूल: लागत मामूली रूप से बढ़ती है (<2x), **किंडरगार्टन प्रवेश पर** फ्रंट-लोडेड मूल्य निर्धारण का सुझाव देती है।

3. **इक्विटी मुद्दा:**
   - प्राथमिक और उच्च स्तरों पर, लागत अंतर कम हो जाता है (11x → 4.5x ग्रामीण, 11x → 6x शहरी), लेकिन **प्रवेश बाधा खड़ी रहती है**।

स्थैतिक पृष्ठभूमि (जीएस II और जीएस I लिंकेज)

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्षों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (RTE) का अधिकार।
  - DPSPs: अनुच्छेद 41 (शिक्षा), अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा)।
- **आरटीई अधिनियम, 2009:** 6-14 वर्ष को कवर करता है, पूर्व-प्राथमिक को कानूनी गारंटी के बाहर छोड़ देता है।
- **नीतिगत ढांचा:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 **2030 तक** ईसीसीई (प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा) तक सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देती है।
- **सामाजिक-आर्थिक संदर्भ:** पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सीखने की नींव का निर्माण करती है; उच्च लागत जोखिम कमजोर **वर्गों के बहिष्करण और** असमानताओं को गहरा करती है।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **लागत का फ्रंट-लोडिंग:** निजी स्कूल किंडरगार्टन में अनुपातहीन रूप से उच्च शुल्क लेते हैं, माता-पिता को जल्दी बंद कर देते हैं और उच्च कक्षाओं में प्रतिधारण सुनिश्चित करते हैं।
2. **इक्विटी संबंधी चिंताएं:** प्री-प्राइमरी आरटीई के तहत कवर नहीं किया गया है; इसलिए, निजी कंपनियां नियामक शून्य का फायदा उठाती हैं। गरीब परिवार या तो वित्त पर बोझ डालते हैं या पूरी तरह से सरकारी आंगनवाड़ियों पर निर्भर हैं।
3. **गुणवत्ता बनाम लागत विरोधाभास:** अध्ययनों से पता चलता है कि निजी स्कूलों में सीखने के परिणाम **सरकारी स्कूलों की तुलना में काफी अधिक** नहीं हैं , जिससे अधिक मूल्य निर्धारण का संदेह बढ़ जाता है।
4. **क्षेत्रीय असमानताएं:** कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्य **खतरनाक गुणक दिखाते** हैं, जो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति का सुझाव देते हैं।
5. **शासन और विनियमन:** पूर्व-प्राथमिक स्तर पर कमजोर शुल्क विनियमन, अंग्रेजी-माध्यम/निजी स्कूली शिक्षा के लिए माता-पिता की आकांक्षा के साथ, अत्यधिक शुल्क को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शामिल करने के लिए** आरटीई कवरेज का विस्तार करना, समान प्रारंभिक प्रारंभिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और शिक्षाशास्त्र के साथ** आंगनवाड़ियों और ईसीसीई केंद्रों को मजबूत करना।
- **राज्य स्तरीय स्कूल नियामक प्राधिकरणों द्वारा निजी किंडरगार्टन के लिए** शुल्क विनियमन।
- **सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए** जागरूकता अभियान।
- **महंगी निजी स्कूली शिक्षा पर निर्भरता कम करने के लिए एनईपी 2020 के अनुसार** ईसीसीई में सार्वजनिक निवेश।

निष्कर्ष

सीएमएस शिक्षा 2025 सर्वेक्षण इस बात को रेखांकित करता है कि **भारत की स्कूली शिक्षा असमानताएं पूर्व-प्राथमिक चरण में ही निहित हैं**। अनुपातहीन रूप से उच्च निजी किंडरगार्टन शुल्क एक प्रवेश बाधा के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक-आर्थिक विभाजन को गहरा करता है। जब तक प्रारंभिक बचपन की शिक्षा **को किफायती, विनियमित और सार्वभौमिक** नहीं बनाया जाता है, तब **तक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा (एसडीजी 4)** का लक्ष्य दूर रहेगा। इस अंतर को पाटना केवल शिक्षा नीति का मामला नहीं है - यह एक संवैधानिक और विकासात्मक अनिवार्यता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वेक्षण से पता चलता है कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच लागत का अंतर पूर्व-प्राथमिक स्तर पर सबसे बड़ा है।

2. सरकारी स्कूलों के विपरीत निजी स्कूलों में स्कूली शिक्षा के क्रमिक स्तरों पर खर्च तेजी से बढ़ता है, जहां यह स्थिर रहता है।

3. कर्नाटक ने शहरी क्षेत्रों में निजी-सरकारी किंडरगार्टन लागत अंतर के उच्चतम गुणकों में से एक दर्ज किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

ए) केवल 1

b) केवल 1 और 3

c) केवल 2 और 3

डी) 1, 2 और 3

उत्तर: बी)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: भारत में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए संवैधानिक और नीतिगत ढांचे की जांच करें। सरकार सस्ती और न्यायसंगत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है? **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

Iran and India, ancient civilisations and new horizons

Iraj Elahi

is the Ambassador of the Islamic Republic of Iran to India

The world is undergoing a profound change. Many call this a "time of transition," while others label it as a "crisis of the Western-led international order.". What is clear is that the global system, long dominated by western powers, especially the United States, now faces serious challenges.

We see blatant violations of international law, the unchecked use of force, trade wars, a disregard for global institutions, manipulation of the media, and irreversible destruction of the environment. These are not isolated incidents but signs of a deeper crisis. The West, led by the U.S., no longer holds the same ability to dictate its own will as it once did. Its classic toolkit of dominance – the global financial system, monopoly over science and technology, imposition of so-called human rights standards, and control of global media is losing its effectiveness.

The Global South is on a new path

Nations are awakening. Countries, particularly in the Global South, refuse to remain under domination and discrimination. By relying on local models, developing indigenous science and technology, and strengthening their defence and security, they have begun a new path.

In this historic transformation, ancient civilisations hold a unique role. Iran and India, two of the world's oldest and richest civilisations, have, for centuries, shaped global culture. Both civilisations valued peace and avoided war, fighting only in defence against aggression. Even when defeated militarily, their cultural influence was so profound that they reshaped the conquerors, imparting their knowledge of statecraft, governance, literature, philosophy, and art and architecture to them.

After the arrival of Islam, Iran's civilisational values continued in a new form, while India – recognised as the oldest continuous civilization – was further enriched by Islamic influence. Shared ancient values have endured across centuries: the view of life as a gift, the belief in the ultimate triumph of good over evil, respect for diversity, the pursuit of inner purification, and the commitment to spiritual growth.

Modern history shows the same resilience. India, through its anti-colonial struggle and leadership of the Non-Aligned Movement, defended the rights of the Global South. Iran, by nationalising its oil industry and through the Islamic Revolution, resisted western domination. Together, both nations embody values that are urgently needed today: peace, spirituality and respect for nature – values that can guide humanity in facing structural violence, environmental crises and social collapse.

Of course, this independence has come at a price. For decades, Iran has endured economic terrorism, cognitive warfare and relentless external interference, yet, it has never yielded. India, too, has faced unjustified pressures and hostile measures. But neither nation has sacrificed its identity or independence to the ambitions of dominant powers.

Now is the time for ancient civilisations such as Iran and India to chart a new course for the Global South. By strengthening South-South cooperation, playing an active role in frameworks such as BRICS, upholding human and moral principles, and advancing transformative projects such as the International North-South Transport Corridor (INSTC), India and Iran can together build the foundations of a just and humane order.

> With their civilisational wisdom, strategic independence and constructive partnership, Tehran and New Delhi can give the changing world a new order

The Palestine issue

At the heart of this order lies the struggle for Palestine – the foremost concern of the Global South. Nowhere else is the hypocrisy, the supremacism and the brutality of the West more evident. The Palestinian people, standing on the front lines against occupation and expansionism, are in fact fighting for the right of all Global South nations to resist domination. In the same way, Iran's defence of its right to peaceful nuclear energy is also a defence of the South's right to development. At the same time, Iran becomes a stronghold for international law, diplomacy and dialogue against those who claim to uphold human rights and democracy, yet constantly violate law and order.

Multilateral organisations such as BRICS hold great potential to challenge the economic dominance of the West. At a time when economic sanctions and trade wars are being used to impede development and prevent de-dollarisation, BRICS offers the promise of an independent, participatory and democratic future. Likewise, the INSTC corridor is more than an economic route. It is a civilisational bridge, linking Eurasia, the Caucasus, India and Africa, while bringing stability to West Asia.

The U.S.'s interventions

In West Asia, the U.S. and its allies have consistently sought to prevent the emergence of indigenous regional security by supporting the Zionist regime and fuelling instability in Palestine, Lebanon, Iraq, Syria, Yemen and Iran. Iran, as the region's oldest civilisation, has firmly opposed such interventions and stands firmly against threatening the territorial integrity of the sovereign countries of the West Asia region.

In South Asia as well, the U.S. has played a major role in creating and expanding terrorist groups. Whenever it has served its interests, Washington has intervened under the pretext of fighting terrorism. And whenever it has suited its agenda, it has even handed power back to those very terrorist groups.

Today, we stand at a turning point in history. The world is changing. Emerging powers and ancient civilisations are redefining their roles. Iran and India, through civilisational wisdom, strategic independence and constructive partnership, can offer the world a new model: an order that is rooted in justice, common interests and respect for human dignity.

This is an order based not on domination, but on participation; not on superiority, but equality. It is a future where nations are not tools of the powerful, but builders of their own destiny. And who better than ancient civilisations such as Iran and India to lead humanity toward such a future?

जी एस। पेपर 02 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूपीएससी मुख्य अभ्यास प्रश्न: जांच करें कि भारत और ईरान समकालीन बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सभ्यतागत संबंधों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डाल सकती हैं? (150 शब्द)

संदर्भ:

भारत और ईरान, दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में से एक हैं, एक **सहस्राब्दी पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध** साझा करते हैं। राजदूत इराज इलाही उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विशेष रूप से **ग्लोबल साउथ में इन देशों की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं**, क्योंकि पश्चिमी प्रभुत्व संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह तर्क **समकालीन वैश्विक संकटों के जवाब में** सभ्यतागत निरंतरता, रणनीतिक स्वतंत्रता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर देता है।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **वैश्विक प्रणाली संक्रमण:**
    - अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रभुत्व की प्रभावशीलता में गिरावट: वित्तीय प्रणाली, मीडिया, प्रौद्योगिकी, मानवाधिकार प्रवचन।
    - संरचनात्मक संकट: व्यापार युद्ध, जलवायु परिवर्तन, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष।
2. **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:**
    - भारत और ईरान आर्थिक और सभ्यतागत एकीकरण के लिए **ब्रिक्स** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी)** जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठा सकते हैं।
    - परमाणु ऊर्जा के अधिकारों की रक्षा और प्रतिबंधों के प्रतिरोध को वैश्विक दक्षिण संप्रभुता की रक्षा के रूप में तैनात किया गया है।
3. **सभ्यतागत निरंतरता:**
    - साझा मूल्य: शांति, विविधता के लिए सम्मान, आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक लचीलापन।
    - ऐतिहासिक उदाहरण: भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्व, ईरान का तेल राष्ट्रीयकरण और इस्लामी क्रांति।
4. **भू-राजनीतिक मुद्दे:**
    - फिलिस्तीन संघर्ष को वैश्विक दक्षिण न्याय के लिए एक केंद्रीय चिंता के रूप में उजागर किया गया।
    - पश्चिम एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप की आलोचना, और प्रॉक्सी या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से दक्षिण एशिया की अस्थिरता।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **भारत-ईरान संबंध:**
    - 1950 के दशक से राजनयिक संबंध; 1990 के दशक के बाद ऊर्जा और व्यापार सहयोग को मजबूत किया गया।
    - INSTC: भारत, ईरान, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला बहु-मॉडल परिवहन मार्ग।
    - रणनीतिक संरेखण: ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, क्षेत्रीय संपर्क।
- **ग्लोबल साउथ:**

- यह अवधारणा 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक/नव-औपनिवेशिक वर्चस्व का विरोध करने वाले विकासशील देशों के गठबंधन के रूप में लोकप्रिय हुई।
- प्लेटफार्म: एनएएम (ऐतिहासिक), ब्रिक्स, एससीओ (समकालीन)।

- **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था:**
  - अमेरिका के एकध्रुवीय प्रभुत्व में गिरावट; क्षेत्रीय शक्तियों (भारत, चीन, ब्राजील, ईरान) का उदय।
  - समान वैश्विक शासन **का आह्वान**: आईएमएफ/डब्ल्यूबी सुधार, वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली, क्षेत्रीय सुरक्षा स्वायत्तता।

मेन्स के लिए विश्लेषण

1. **रणनीतिक अवसर:**
   - सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध व्यापार, संस्कृति और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क (आईएनएसटीसी, चाबहार बंदरगाह) को मजबूत कर सकते हैं।
   - ब्रिक्स और क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग पश्चिमी नेतृत्व वाली प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।
2. **मानक अपील:**
   - भारत और ईरान **विश्व मामलों में** न्याय, समानता और मानवीय गरिमा पर जोर देते हैं।
   - भागीदारी और न्यायसंगत शासन की **वकालत करते हुए प्रभुत्व-आधारित वैश्विक व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करता** है।
3. **चुनौतियों:**
   - भू-राजनीतिक बाधाएं: ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा राजनीति।
   - घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करना।
4. **सभ्यतागत कूटनीति:**
   - साझा इतिहास और संस्कृति को ग्लोबल साउथ में प्रभाव के लिए एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में आमंत्रित करता है।
   - इस बात पर जोर दिया कि ऐतिहासिक लचीलापन आधुनिक रणनीतिक नीति और बहुपक्षीय जुड़ाव को सूचित करता है।

निष्कर्ष

राजदूत की कहानी भारत और ईरान को एक पुनर्परिभाषित वैश्विक व्यवस्था के लिए **लंगर सभ्यताओं के रूप में** स्थापित करती है - जो न्याय, समानता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में निहित है। भारत के लिए, यह रणनीतिक **स्वायत्तता, बहुध्रुवीय कूटनीति और सभ्यतागत सॉफ्ट पावर के साथ संरेखित है**, जो 21वीं सदी में अपनी वैश्विक भूमिका को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक संबंधों, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और ब्रिक्स और आईएनएसटीसी जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर, भारत और ईरान अधिक **न्यायसंगत, टिकाऊ और सहभागी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में योगदान कर सकते हैं**।

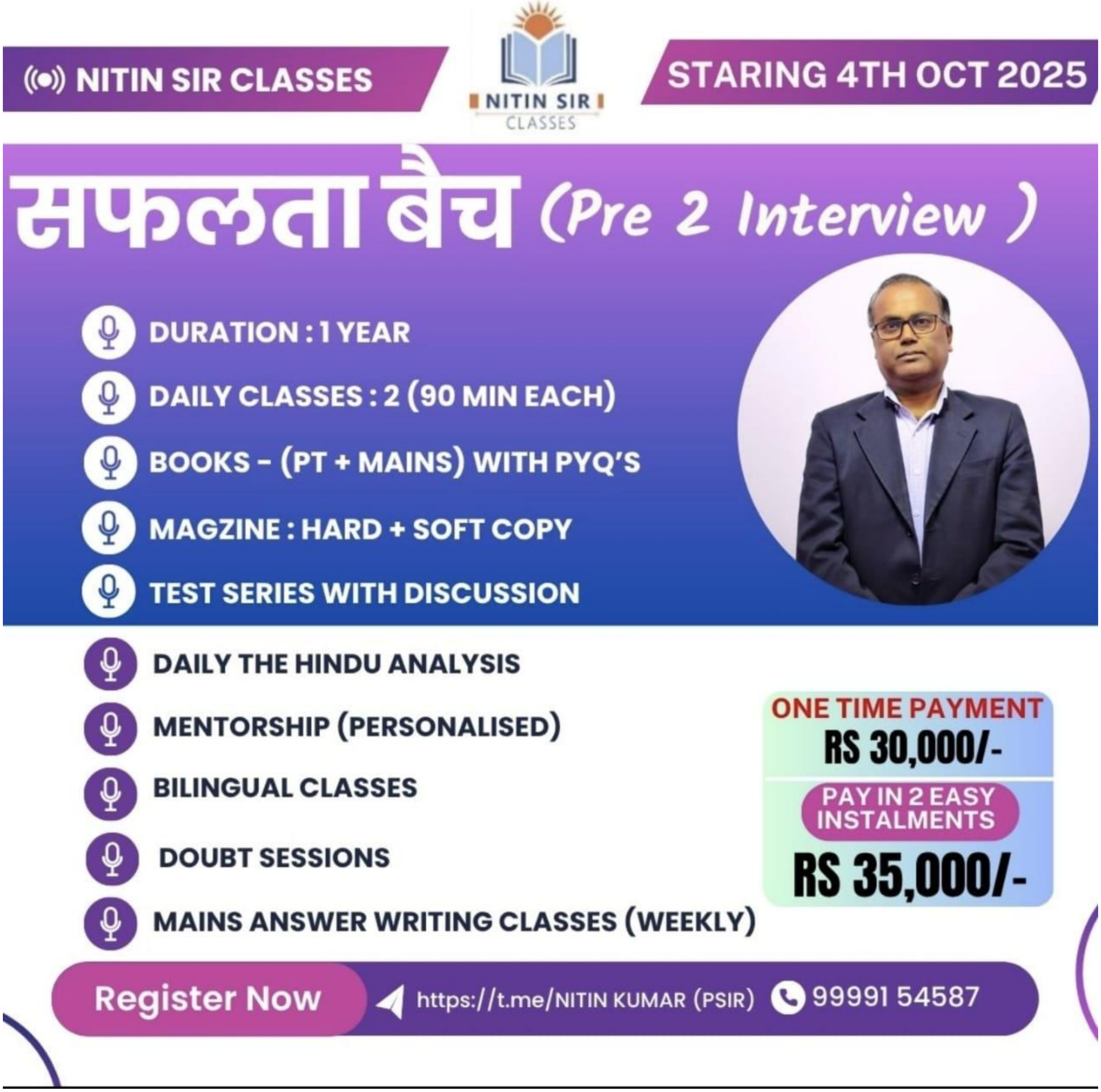
NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
सफलता बैच (Pre 2 Interview)
DURATION : 1 YEAR
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)
ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
आधार बैच (Aadhaar Batch)
DURATION : 2 YEARS
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
NCERT FOUNDATION
SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
TEST SERIES WITH DISCUSSION
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES
ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)
DURATION : 7 MONTH
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
KNOW YOUR TEACHERS
Nitin sir Classes
GS PAPER I
HISTORY + ART AND CULTURE
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
GS PAPER I
SOCIETY + SOCIAL ISSUES
NITIN KUMAR SIR
SHABIR SIR
GS PAPER II
POLITY + GOVERNENCE + IR + SOCIAL JUSTICE
NITIN KUMAR SIR
GS PAPER I
GEOGRAPHY
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ANUJ SINGH SIR
GS PAPER III
ECONOMICS
SCI & TECH
SHARDA NAND SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
GS PAPER III
INTERNAL SECURITY + ENG. (MAINS)
ARUN TOMAR SIR
GS PAPER III
ENVIRONMENT & ECOLOGY AND DISASTER MANAGEMENT
DHIPRAGYA DWIVEDI SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
GS PAPER IV
ETHICS AND APTITUDE + ESSAY + CURRENT AFFAIRS
NITIN KUMAR SIR
CSAT
YOGESH SHARMA SIR
OPTIONAL
HISTORY
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
OPTIONAL
GEOGRAPHY
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
OPTIONAL
PSIR + PUBLIC ADMINISTRATION
NITIN KUMAR SIR
OPTIONAL
SOCIOLOGY
SHABIR SIR
OPTIONAL
HINDI LITERATURE
PANKAJ PARMAR SIR
https://www.facebook.com/ nitinsirclasses
https://www.youtube.com/@nitinsirclasses8314
http://instagram.com/k.nitinca
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)

Follow More:-

- **Phone Number :- 9999154587**
- **Email :-** k.nitinca@gmail.com
- **You Tube : -** **https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram : -** **https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook:https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : -** **https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**